

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 10 जुलाई, 2007

विषय: जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर में सिविल जज(जू०डि०) के न्यायालय भवन(अनावासीय) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-383/यू०एच०सी०/एडमिन(बी)/निर्माण/2006, दिनांक 12.2.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर में सिविल जज(जू०डि०) के न्यायालय भवन(अनावासीय) के निर्माण हेतु रु० 68,22,000/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 66,20,000/- (छियासठ लाख बीस हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 66,20,000/- (छियासठ लाख बीस हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदुपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) इस धनराशि के पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाय ।
- (3) कार्य एक निश्चित समयावधि में समाप्त हो, इसके लिए निर्माण इकाई समयान्तर्गत पूरे कार्य का टेण्डर प्रकाशित करते हुए ठेकेदार से हुए अनुबन्ध की प्रति शासन में उपलब्ध कराये ।
- (4) निर्माण इकाई धनराशि प्राप्त करने के तीन माह के अन्दर टेण्डर प्रकाशित करते हुए कार्य समाप्त होने के निश्चित समयावधि से शासन को अवगत कराते हुए इसका प्रमाण-पत्र शासन में उपलब्ध कराये ।
- (5) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदुपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (6) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (7) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।
- (8) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन को कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।
- (9) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मददेनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

- (10) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (11) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (12) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (13) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (14) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051 निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-694/XXVII(5)/2007, दिनांक 4.7.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

( आर०डी०पालीवाल )  
सचिव ।

संख्या-5-दो(8)/XXXVI(1)(2)/2007-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/टिहरी गढ़वाल ।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशाली अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, मुख्यालय कीर्तिनगर ।
7. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
8. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( आलोक कुमार वर्मा )  
अपर सचिव ।